(Post-Cold ...)

Paper-VI Dr. Khalid

माओ के बाद के काल में चीनी विदेश नीति
(Chinese Foreign Policy in the Post-Mao Period)

1990 वाले दशक में शीतयुद्ध के अन्त

1976 में माओ की मृत्यु के समय से लेकर अबतक चीनी विदेश नीति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व (Elements of continuity and change) देखने को मिलते हैं। निरंतरता के तत्व इस तथ्य के परिणाम हैं कि शीतयुद्ध माओ के बाद के काल में चीनी भी वैदेशिक नीति के लक्ष्य बुनियादी रूप से वही हैं जो माओ के जमाने में थे। वे लक्ष्य हैं:— (i) राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राप्ति तथा (ii) चीन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय जगत में एक महत्वपूर्ण एवं महान राष्ट्र के दर्जे की प्राप्ति। परंतु साथ ही साथ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की परिस्थितियों तथा शीतयुद्ध माओ के बाद चीन के नीति-निर्धारकों की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की परिस्थितियों तथा उन परिस्थितियों में चीन की स्थिति के सम्बंध में समझदारी में परिवर्तन के चलते हेरफेर एवं समायोजन (Shifts and readjustments) होते रहे हैं। 1980 वाले दशक के प्रारम्भ में चीन की आंतरिक राजनीति में 'Four Modernisations' की नीति का शीतयुद्ध के बाद के काल में भी अवलम्बन हो रहा है। इस नीति के अनुरूप विदेशनीति में Shifts and readjustments लाये गये हैं।

1990 वाले दशक के प्रारंभ में शीतयुद्ध के अन्त, सोवियत संघ सहित अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों में से साम्यवादी व्यवस्था के अंत, सोवियत संघ का एक राष्ट्र के रूप में अन्त, तथा पूर्व सोवियत संघ के सबसे बड़े उत्तराधिकारी रूस एवं पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते सहयोग आदि तथ्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की परिस्थितियों में भारी परिवर्तन ला दिया। विश्व के अधिकांश देशों की भाँति चीन के नीतिनिर्धारकों के सामने भी उन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की चुनौती उपस्थित हो गई। ~~अत~~ इन बदलती हुई परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास के क्रम में नीतिनिर्धारकों ने ~~माओ~~ फिर से Shifts and readjustments (हेरफेर एवं समायोजन) लाये हैं और ला रहे हैं।

~~Mao के बाद की चीनी विदेशनीति के सम्बन्ध में उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए~~

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए शीतयुद्ध Mao के बाद की चीनी विदेशनीति की मुख्य प्रवृत्तियों (तत्वों, विशेषताओं) को रेखांकित किया जा सकता है:—

[Mao के बाद की चीनी विदेशनीति जैसाकि चीनी साम्यवादी पार्टी के मुख्य नेता Yaobang ने 1982 में घोषित किया, की एक महत्वपूर्ण विशेषता विदेशनीति

SHOT ON REDMI
AI DUAL CAMERA

Scanned with CamScanner

की स्वतंत्रता (Independence of foreign policy) है। विदेश नीति की स्वतंत्रता से चीनी नेतृत्व का तात्पर्य यह था कि चीन दोनों महाशक्तियों (USA तथा सोवियत संघ) — USA and Soviet Union — में से किसी के साथ सैनिक दृष्टि से सम्बद्ध नहीं होगा या अन्य देशों के साथ सम्बद्ध नहीं होगा। Mao के नेतृत्व में चीन ने पहले USA के विरुद्ध United Front (संयुक्त मोर्चे) की रणनीति एवं संघर्ष की रणनीति अपनाई और बाद में USA USSR के विरुद्ध ऐसी रणनीति का अवलंबन किया। 1980 वाले दशक के प्रारंभ में जिस नीति का अवलंबन किया, उसके अन्तर्गत दोनों में से किसी एक महाशक्ति के साथ घनिष्ठ सम्बंध की स्थापना तथा दूसरे के विरुद्ध संघर्ष की नीति का परित्याग कर दिया गया। इसीलिए 1980 वाले दशक के प्रारंभ से 1989 में सोवियत संघ के विघटन के समय तक चीन ने USA के साथ अच्छे सम्बंध बनाये रखते हुए USSR के साथ भी अपने सम्बंधों को सुधारने का पूर्ण प्रयास किया। China तथा USSR दोनों ने यह स्वीकार किया कि उनकी राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं में कोई मौलिक अंतर नहीं है। इसी साथ ही, उसने Sino-US relations में (चीन-अमेरिका सम्बंधों में सुधार की सीमाओं को भी महसूस किया। USSR के साथ सम्बंध सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इसके मार्ग में उपस्थित बाधाओं को दूर करने में China ने सोवियत संघ के साथ सहयोग किया।

1990 वाले दशक में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की परिस्थितियों में बुनियादी परिवर्तनों से यद्यपि चीन चिंतित एवं दुखी था, तथापि उसने उन परिवर्तनों को रोक पाने में अपनी अक्षमता तथा एवं अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिकता का परिचय दिया। चीन के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए USA तथा अन्य पश्चिमी देशों के सहयोग की आवश्यकता थी। उधर सोवियत संघ से साम्यवादी व्यवस्था के अंत, एक राष्ट्र के रूप में उसके विघटन के तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में पूर्व सोवियत संघ के सबसे बड़े उत्तराधिकारी रूस द्वारा पश्चिमी देशों के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण के चलते चीन को वह लाभदायक स्थिति नहीं रह गई जो शीत युद्ध के काल में थी। ऐसी स्थिति में USA तथा अन्य पश्चिमी देशों के साथ अपने मतभेदों को उजागर करने के बजाय चीन मोटे तौर पर पश्चिमी देशों के साथ

SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA
Scanned with CamScanner

शीतयुद्ध के अंत के बाद यद्यपि चीन ने शुरू में पश्चिमी देशों के साथ सहयोग की नीति की घोषणा की और कई मामलों में उनके साथ सहयोग भी किया, परन्तु यह सहयोग अधिक आगे नहीं बढ़ सका। चीन ने यह महसूस किया है कि सोवियत संघ के अंत के बाद उसके प्रति USA का रुख कड़ा होने लगा है। USA के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने चीन में मानवाधिकारों के हनन का मुद्दा बार-बार उठाया है। ऐसी स्थिति में चीनी नेतृत्व की यह भावना है कि पश्चिमी देश चीन की राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन के महत्वपूर्ण स्थान का अंत देखना चाहते हैं। चीन में कई सुरक्षा विशेषज्ञों (Security Specialists) ने यह विचार व्यक्त किया है कि शीतयुद्ध के बाद के काल में (Post-Cold War Period) में USA एक arrogant nation (घमंडी राष्ट्र) जैसा व्यवहार कर रहा है और पूरी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में वह अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। पिछले 10-12 वर्षों में चीनी विदेश नीति इस बात से सम्बन्धित रही है कि कैसे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में USA के बढ़ते हुए वर्चस्व को रोका जाए। Russia तथा France के साथ मिलकर USA के प्रभाव को रोकने के लिए सहमति को बढ़ाने के सम्बन्ध में चीनी प्रयास को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

शीतयुद्ध के अंत के पूर्व पूर्ववर्ती सोवियत संघ तथा USA के बीच तनावशैथिल्य की जो प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी, उसके प्रति 1980 वाले दशक के प्रारंभ में सकारात्मक दृष्टिकोण (Positive Approach) अपनाया था। यह उल्लेखनीय है कि 1970 वाले दशक में चीन ने USA-USSR Detente (अमेरिका-सोवियत संघ तनावशैथिल्य) की प्रक्रिया के प्रति आशंका व्यक्त की थी। परंतु 1980 वाले दशक के प्रारंभ से चीन ने यह विचार व्यक्त करना प्रारंभ किया कि Detente से अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। चीन ने दोनों देशों से आणविक हथियारों के लिए होड़ पर रोक लगाने की भी अपील की। Detente तथा निरस्त्रीकरण प्रति यह नवीन दृष्टिकोण अवश्यम्भावी युद्ध के सिद्धांत सम्बन्धी माओ के सिद्धांत से भिन्न था।

1980 वाले दशक में Theory of Three Worlds (तीन दुनिया के सिद्धांत) पर बल देते हुए चीन ने तृतीय विश्व अर्थात विकासशील देशों के साथ सम्बन्ध सुधार का भरपूर प्रयास किया। तृतीय विश्व के देशों में क्रांतिकारी गतिविधियों को

पड़ोसी देशों अपनी पुरानी नीति का परित्याग किया है। यद्यपि Three worlds (तीन दुनिया) के सिद्धांत का प्रतिपादन Mao ने ही किया था, परंतु उसके आधार पर विकासशील देशों में चीन की छवि सुधारने तथा उनके साथ अपने सम्बंधों को सुदृढ़ बनाने का प्रयास माओ के बाद के नेतृत्व ने किया है। शीत युद्ध के बाद के काल में Theory of Three worlds यद्यपि बहुत प्रासंगिक नहीं रह गया है, तथापि विकासशील देशों के साथ सम्बंध सुधारने तथा उनके हितों ~~के रक्षा~~ के हिमायती के रूप में अपने को पेश करने का प्रयास Post-Cold War Period में भी जारी है। भारत ~~और देशों~~ तथा अन्य विकासशील देशों के साथ World Trade Organisation तथा अन्य आर्थिक संस्थाओं में विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाना चीनी विदेश नीति का प्रमुख निर्धारक रहा है।

1990 वाले दशक में चीनी वैदेशिक नीति में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति उभर कर सामने आई है। अपने पड़ोसी देशों के साथ सम्बंधों के सुधार में उसने अधिक अभिरुचि दिखाई है। वियतनाम, दक्षिण कोरिया, भारत तथा जापान ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनके साथ चीन ने अपने सम्बंधों को सुधारने में दिलचस्पी दिखाई है। भारत के सम्बंध सुधार के लिए निश्चित

शीत युद्ध Mao के बाद की चीनी वैदेशिक नीति की अबतक की चर्चा से यह बात सामने आती है कि [Mao की मौत के कुछ दिनों बाद तथा फिर शीतयुद्ध की समाप्ति के संदर्भ में] ~~वै~~ वैदेशिक नीति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आये हैं। चीनी वैदेशिक नीति ~~निर्माण तथा~~ के निर्धारण एवं उन्मुखीकरण (determination and orientation) में Ideology ~~सिद्धांत~~ (विचारधारा) की भूमिका उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई है जितनी 1950 तथा 1960 वाले दशकों में थी। आज निश्चित रूप से चीनी विदेशनीति ~~में व्यवहारवादिता का दिन प्रतिदिन~~ दिनोदिन व्यवहारवादिता (Pragmatism) से अधिक प्रेरित होती जा रही है। ~~चूँकि बदलती हुई परिस्थितियों तथा आधुनी आधुनिकीकरण चूँकि~~ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की बदलती हुई परिस्थितियों तथा चीन के आधुनिकीकरण की मांग के चलते चीन के लिए यह आवश्यक हो गया है कि विचारधारा के स्थान पर व्यवहारवादिता पर बल दे। इसी लिए : "The Chinese foreign policy in the ~~post-Mao~~ post-~~Mao~~ Cold War period has been inspired by pragmatism and ideology has been relegated to the background".

रूप से अपनी वैदेशिक नीति में पर्याप्त लचीलापन ~~दिखाई~~ एवं व्यावहारिकता दिखाई है। ~~Sikkim~~ चीन द्वारा Sikkim को भारत का अंग स्वीकार करना ... अपने सामरिक हितों को ... सम्बंध सुधार की प्रक्रिया ... USA ... ऐसा माहौल बनाए रखना ... सैनिक उपस्थिति ... आवश्यकता ...

[illegible]